



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकरण से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 138]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 30, 1987/चैत्र 9, 1909

No. 138]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 30, 1987/CHAITRA 9, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as
a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1987

आदेश

का.आ. 268(अ) :—/18कक/आई.डी.आर.ए./87—
केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक
विकास मंत्रालय के आदेश सं. का.आ. 134(अ)/18कक/
आई.डी.आर.ए./79, तारीख 13 मार्च, 1979, द्वारा यथा
उपांतरित आदेश सं. का.आ. 529(अ)/18कक/आई.
डी.आर.ए./74 तारीख 6 सितम्बर, 1974 द्वारा (जिसे
इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) सचिव, बंद
रुग्ण उद्योग विभाग पश्चिमी बंगाल सरकार को, (जिसे
अब सचिव, औद्योगिक पुन-निर्माण विभाग, पश्चिमी बंगाल
सरकार कहा गया है) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त
अधिकृत व्यक्ति कहा गया है) मैमर्स इंडिया बैल्टिंग एण्ड
काउन्ट विज़न लिमिटेड, सोरभापुर पश्चिमी बंगाल का (जिसे

इसमें इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है)
तारीख 6 सितम्बर, 1974 से पांच वर्ष की अवधि के
लिये प्रबंध ग्रहण करने के लिये प्राधिकृत किया था।

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में
यह समीचीन है कि उक्त अधिसूचित आदेश को उपयुक्त
पांच वर्ष के समाप्त होने के बाद प्रभावी बना रहना
चाहिये और उसमें 31 मार्च, 1987 तक की, जिसके
अन्तर्गत वह तारीख भी है, अतिरिक्त अवधि के लिये
इसे जारी रखने के लिये समय-समय पर निर्देश जारी किये
थे, (देखिए भारत सरकार के औद्योगिक विकास विभाग) —

सं. का.आ. 512(अ)/18कक/आई.डी.आर.ए./79,
तारीख 4 सितम्बर, 1979,

सं. का.आ. 749(अ)/18कक/आई.डी.आर.ए./80,
तारीख 5 सितम्बर, 1980,

सं. का.आ. 684(अ)/18कक/आई.डी.आर.ए./81,
तारीख 4 सितम्बर, 1981,

सं. का.प्रा. 125(प्र)/18कक/आई.डी.आर.ए./82,
तारीख 5 मार्च, 1982,

सं. का.प्रा. 648(प्र)/18कक/आई.डी.आर.ए./82,
तारीख 4 सितम्बर, 1982,

सं. का.प्रा. 158(प्र)/18कक/आई.डी.आर.ए./83,
तारीख 4 मार्च, 1983,

सं. का.प्रा. 386(प्र)/18कक/आई.डी.आर.ए./83,
तारीख 31 मई, 1983,

सं. का.प्रा. 937(प्र)/18कक/आई.डी.आर.ए./83,
तारीख 29 दिसम्बर, 1983,

सं. का.प्रा. 470(प्र)/18कक/आई.डी.आर.ए./84,
तारीख 28 जून, 1984,

सं. का.प्रा. 947(प्र)/18कक/आई.डी.आर.ए./84,
तारीख 18 दिसम्बर, 1984,

सं. का.प्रा. 257(प्र)/18कक/आई.डी.आर.ए./85,
तारीख 28 मार्च, 1985, तथा

सं. का.प्रा. 119(प्र)/18कक/आई.डी.आर.ए. 86
तारीख 27 मार्च, 1986;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध उक्त प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा 31 मार्च, 1988 तक की और अवधि के लिए जारी रखा जाय;

अतः केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त आदेश 31 मार्च, 1988 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, की और अवधि के लिये प्रभावी बना रहेगा।

[का.सं. 2(14)/80-सी.यू.एस.]

ए.वी. गोकक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 30th March, 1987

ORDER

S.O. 268(E)|18AA|IDRA|87.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 529(E)|18AA|IDRA|74, dated the 6th September, 1974 as modified by the Order No. S.O. 134(E)|18AA|IDRA|79, dated the 13th March, 1979 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government had authorised the Secretary, Closed and Sick Industries Department, Government of West Bengal, now called Secretary,

Industrial Reconstruction Department, Government of West Bengal (hereinafter referred to as the said authorised person) to take over the management of Messrs India Belting and Cotton Mills Limited, Serampore, West Bengal (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) for a period of five years from the 6th September, 1974;

And, whereas, the Central Government being of opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect after the expiry of the period of five years aforesaid, had issued directions from time to time, for such continuance for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1987 (vide Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development)).

Nos. S.O. 512(E)|18AA|IDRA|79, dated the 4th September, 1979,

S.O. 749(E)|18AA|IDRA|80, dated the 5th September, 1980,

S.O. 684(E)|18AA|IDRA|81, dated the 4th September, 1981,

S.O. 125(E)|18AA|IDRA|82, dated the 5th March, 1982,

S.O. 648(E)|18AA|IDRA|82, dated the 4th September, 1982,

S.O. 158(E)|18AA|IDRA|83, dated the 4th March, 1983,

S.O. 386(E)|18AA|IDRA|83, dated the 31st May, 1983,

S.O. 937(E)|18AA|IDRA|83, dated the 29th December, 1983,

S.O. 470(E)|18AA|IDRA|84, dated the 28th June, 1984,

S.O. 947(E)|18AA|IDRA|84, dated the 18th December, 1984,

S.O. 257(E)|18AA|IDRA|85, dated the 28th March, 1985 and

S.O. 119(E)|18AA|IDRA|86, dated the 27th March, 1986;

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the management of the said industrial undertaking by the said authorised person should continue for a further period upto 31st March, 1988;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of 31st March, 1988.

[File No. 2(14)|80-CUS]
A. V. GOKAK, Jt. Secy.